UPSC : सिविल सेवा परीक्षा

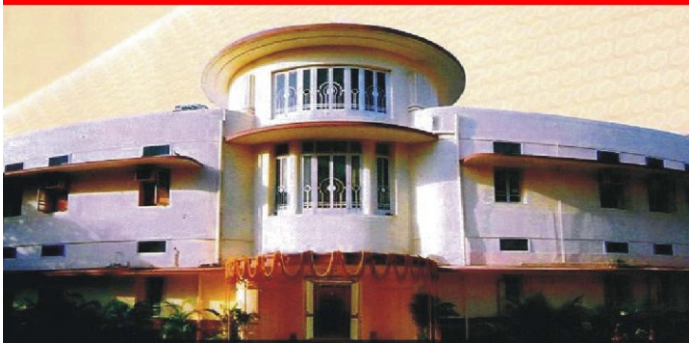

UPSC : सिविल सेवा परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा

सामान्य अध्ययन - I
(200 अंक / 2 घण्टा)
सामान्य अध्ययन - II
(200 अंक / 2 घण्टा)
(केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक)

मुख्य परीक्षा

A. सामान्य अध्ययन - 1000 अंक
- सामान्य अध्ययन - I (250 Mark 3Hrs.)
- सामान्य अध्ययन - II (250 Mark 3Hrs.)
- सामान्य अध्ययन - III (250 Mark 3Hrs.)
- सामान्य अध्ययन - IV (250 Mark 3Hrs.)

B. वैकल्पिक विषय - 500 अंक
- वैकल्पिक विषय प्रश्नपत्र - I (250 Mark 3Hrs.)
- वैकल्पिक विषय प्रश्नपत्र - II (250 Mark 3Hrs.)

C. निबंध (250 Mark 3Hrs.)

D. अनिवार्य विषय - 600 अंक
(केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक)
- अनिवार्य : अंग्रेजी (300 Mark 3Hrs.)
- अनिवाय : भारतीय भाषा (300 Mark 3Hrs.)

साक्षात्कार

275 अंक

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - सामान्य अध्ययन

सा. अध्ययन-I (250 Marks 3 hrs.)
- भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास
- भारतीय समाज
- भारत एवं विश्व का भूगोल

सा. अध्ययन-II (250 Marks 3 hrs.)
- शासन व्यवस्था, संविधान एवं शासन प्रणाली
- सामाजिक न्याय
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सा. अध्ययन-III (250 Marks 3 hrs.)
- आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दे
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- जैव-विविधता, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे
- आंतरिक सुरक्षा

सा. अध्ययन-IV (250 Marks 3 hrs.)

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरूचि

GENERAL STUDIES PAPER-I

INDIAN SOCIETY

by

Dr. S. S. Pandey

Indian Society (UPSC : Syllabus)

- भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ
  Salient features of Indian Society
- भारत की विविधता
  Diversity of India
- महिला एवं महिला संगठन की भूमिका
  Role of Women and women's organization
- जनसंख्या संबंधी मुद्दे
  Population and Associated Issues
- गरीबी एवं विकास संबंधी मुद्दे
  Poverty and Developmental Issues
- शहरीकरण, उनकी समस्याएँ एवं उनके उपाय
  Urbanization, their problems and their remedies
- वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव
  Effects of Globalization on Indian Society
- सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता
  Social empowerment, communalism, regionalism & secularism

GENERAL STUDIES : PAPER – I

भारतीय समाज

Effects of Globalization on Indian Society

वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव

वैश्वीकरण
- आर्थिक संबंधों का वैश्विक विस्तार
- सामाजिक संबंधों का वैश्विक विस्तार
- सांस्कृतिक संबंधों का वैश्विक विस्तार

- भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- भारतीय समाज पर प्रभाव
- सामाजिक न्याय के लक्ष्य पर प्रभाव

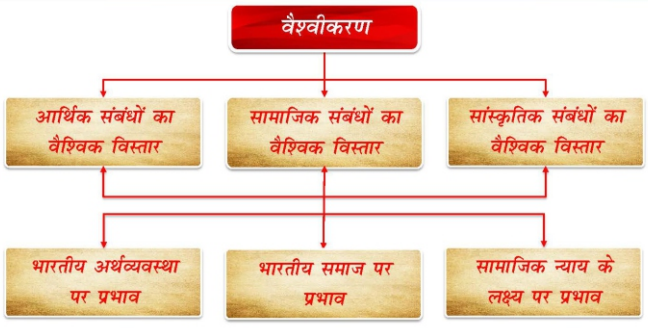

वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव

- भारतीय समाज पर प्रभाव
  - भारतीय संस्कृति पर प्रभाव
  - धर्म पर प्रभाव
  - विवाह व परिवार पर प्रभाव
  - जनजातीय समाज पर प्रभाव
  - महिलाओं पर प्रभाव
  - वृद्धों एवं बच्चों पर प्रभाव
  - श्रमिक वर्ग पर प्रभाव
  - किसान वर्ग पर प्रभाव
  - ग्रामीण समाज पर प्रभाव
  - शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव
- सामाजिक न्याय के लक्ष्य पर प्रभाव
  - सकारात्मक प्रभाव
  - नकारात्मक प्रभाव
    - सीमांतीकरण फलतः अतिवाद (Extremism) का उद्भव एवं आंतरिक सुरक्षा को खतरा

भारतीय अर्थव्यवस्था

- अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं विकास क्रम
- स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप
- आर्थिक विकास का मॉडल / स्वरूप
- स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप/दिशा

अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं विकासक्रम
Meaning and Evolution of Economy

1. खाद्य संकलन एवं शिकारी अर्थव्यवस्था
   Food gathering and hunter-gatherer Economy
2. कृषि अर्थव्यवस्था
   Agricultural Economy
3. औद्योगिक अर्थव्यवस्था
   Industrial Economy

आर्थिक विकास का मॉडल / स्वरूप
Model of Economic Development

1. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
   Capitalist Economy
2. समाजवादी अर्थव्यवस्था
   Socialist Economy
3. मिश्रित अर्थव्यवस्था
   Mixed Economy

स्वतंत्रतापूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप
Nature of Indian Economy before Independence

1. कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था
2. सरल कृषि
3. शोषण पर आधारित अर्थव्यवस्था
   - औद्योगीकरण की शुरूआत
   - अंग्रेजों की औद्योगिक नीति अंग्रेज उद्योगपतियों के पक्ष में और शोषण पर आधारित

स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप / दिशा
Nature/direction of Indian Economy after Independence

1. कृषि अर्थव्यवस्था
2. औद्योगिक अर्थव्यवस्था
3. सामाजिक न्याय से युक्त आर्थिक विकास पर बल

स्वतंत्रता के बाद व 1991 के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था

1. महालनोबिस मॉडल (Mahalanobis Model) के आधार पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) के तहत, सामाजिक न्याय (Social Justice) से युक्त आर्थिक विकास हेतु प्रयास प्रारम्भ
2. लाईसेंसिंग / परमिट प्रणाली (Licensing / Permit System) के अधीन औद्योगिक विकास
3. औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम-1951
   - क्षेत्रीय असंतुलन (Regional Imbalance) को कम करना
   - छोटे उद्यमियों (Small Entrepreneurs) को प्रोत्साहन देना
   - आर्थिक संकेन्द्रण (Economic Concentration) को रोकना (MRTP Act-1969)
4. कठोर श्रम कानून (Strict Labor Laws) के पालन पर बल
5. कठोर राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) पर बल
6. बंद व्यापार व निवेश नीति (Closed Trade and Investment Policy) पर बल
   - आयात प्रतिस्थापन नीति (Import Substitution Policy)
   - FERA - 1973
   - विदेशी बैंक के प्रवेश पर रोक

1991 का आर्थिक सुधार/वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि

1. महालनोबिस मॉडल के कारण सार्वजनिक क्षेत्र घाटे में
2. कठोर लाईसेंसिंग प्रणाली व श्रम कानून के कारण निजी क्षेत्र का विकास बाधित
3. विदेशी निवेश के प्रति नकारात्मक रूख के कारण अवसंरचनात्मक विकास एवं आर्थिक विकास बाधित (Infrastructural Development and Economic Growth)

उपरोक्त स्थितियों और कुछ तात्कालिक परिस्थितियों [जैसे- आन्तरिक व विदेशी कर्ज का बढ़ जाना; रूस का विघटन एवं खाड़ी संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव; दो चुनाव का खर्च, दो सरकार का गिर जाना एवं पूर्व प्रधानमंत्री (राजीव गाँधी) की हत्या के कारण आर्थिक बोझ एवं राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि; International Credit Rating Agency द्वारा भारत के Credit Rating को नीचे गिराना;

फलतः NRI द्वारा अपने जमा का तीव्र निकासी और कर्जदाताओं द्वारा कर्ज देने से इंकार आदि] के परिणमस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में।

फलतः जुलाई 1991 में भारत– IMF – World Bank के बीच Washington सहमति पर हस्ताक्षर और आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ।

आर्थिक सुधार का अर्थ/स्वरूप/लक्षण

IMF एवं World Bank के निर्देशों के अनुसार भारतीय अर्थव्यस्था के स्वरूप में किये गये परिवर्तन को आर्थिक सुधार/वैश्वीकरण की संज्ञा दी जाती है, जो मुख्यतः दो सिद्धान्तों पर आधारित है:–

- स्थिरीकरण का सिद्धान्त (Theory of Stabilization) (IMF)
  1. मुद्रास्फीति (Inflation) को रोकने पर बल
  2. राजकोषीय समायोजन एवं बजट घाटा कम (Fiscal Adjustment and Reduced Budget Deficit) करने पर बल
  3. भुगतान संतुलन (Balance of Payments) को अनुकूल बनाने पर बल

- संरचात्मक समायोजन का सिद्धान्त (Theory of Structural Adjustment) (WB)
  1. व्यापार व पूँजी प्रवाह (Trade and Capital Flows) को तीव्र करने पर बल
  2. औद्योगिक नियंत्रण को समायोजित कर निजीकरण को प्रोत्साहन
  3. सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार पर बल

4. बैंकिग क्षेत्र में सुधार पर बल (नरसिंहम् समिति)

इस प्रकार उपरोक्त आर्थिक सुधार में तीन तत्व केन्द्रीय रहें–

1. उदारीकरण (Liberakusation)
2. निजीकरण (Privatisation)
3. वैश्वीकरण (Globalisation)

1991 के आर्थिक सुधार के प्रमुख प्रभाव

1. राज्य के हस्तक्षेप में कमी व निजीकरण पर बल के कारण ढेर सारी देशी व विदेशी निजी कंपनीयों का भारत के आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश तथा औद्योगीकरण तीव्र एवं विकास तीव्र (Rapid Industrialization and Rapid Development)

2. व्यावसायिक विविधता (Occupational Diversity) में वृद्धि, रोजगार के अवसर में वृद्धि, उत्पाद की मात्रा व गुणवत्ता में वृद्धि और उपभोक्ता बाजार (Consumer Market) का विकास एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि

3. निजी कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों को बेचने के लिए संचार साधनों का प्रयोग और महत्वाकांक्षा को बढ़ाकर उपभोक्तावादी संस्कृति (Culture of Consumer) का विकास

4. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों के वैश्विक विस्तार के कारण, पश्चिमी संस्कृति (Western Culture) का प्रसार, मास संस्कृति (Mass Culture) का विकास, मॉल संस्कृति (Mall Culture) का विकास

5. राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप (Public Welfare State) कमजोर होने से वंचित समूह का सीमांतीकरण (Marginalization of Disadvantaged Groups)

Dr. S. S. Pandey
KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR